EDU TERIA

E - D.N.A

Daily Newspaper Analysis

Prelims Mains Essay

By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 09 January 2026

आइएएएफ वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप में हिमा ने जीता था सोना

धाविका हिमा दास का जन्म 2000 में आज ही असम में हुआ था। बचपन में वह फुटबालर बनना चाहती थीं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर कई शानदार प्रदर्शनों के बाद 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया। फिनलैंड में आइएएएफ वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप 2018 में अंतरराष्ट्रीय ट्रैक स्पर्धा में सोना जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनकर भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। इसी वर्ष जकार्ता में एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। फाइनल में उन्होंने 50.79 सेकेंड का समय लिया, जो अब तक का राष्ट्रीय रिकार्ड है।

Dainik Jagaran Page

पहली व्यावहारिक फोटोग्राफिक प्रक्रिया डाग्यूरोटाइप की घोषणा हुई

1839 में आज ही के दिन फ्रांसीसी विज्ञान अकादमी ने लुई डाग्यूरे द्वारा विकसित पहली व्यावहारिक फोटोग्राफिक प्रक्रिया डाग्यूरोटाइप की घोषणा की थी। चांदी की परत चढ़ी तांबे की प्लेटों का उपयोग करके स्थायी चित्र बनाने वाली इस तकनीक को 19 अगस्त को दुनिया के लिए उपलब्ध किया गया।

फिलिप एस्टली ने दुनिया का पहला आधुनिक सर्कस खोला

1768 में आज ही के दिन पूर्व घुड़सवार व सेना के सार्जेंट मेजर फिलिप एस्टली ने लंदन में पहला आधुनिक सर्कस खोला था। इसमें 42 फीट व्यास के एक रिंग में घुड़सवारी के करतब, कलाबाजी और संगीत का प्रदर्शन किया गया। एस्टली आधुनिक सर्कस के जनक माने जाते हैं।

Dainik Jagaran Page

Sci & Tech

चंद्रमा के पीछे गुरु का ओझल होना आकर्षण का केंद्र होगा | अद्भुत | प्रदूषण वाले शहरों में भी देखी जा सकेंगी घटनाएं

इस वर्ष दिखाई देंगे शानदार खगोलीय नजारे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 जनवरी।

वर्ष 2026 में दक्षिणी आकाश में खगोलीय घटनाओं की भरमार रहेगी अनुकूल समय पर पूर्ण चंद्रग्रहण, ब्लू मून और सुपरमून, दो सबसे चमकीले ग्रहों का एक-दूसरे के बेहद करीब आना और दिन के समय चंद्रमा के पीछे बृहस्पति का ओझल होना खगोलविदों के आकर्षण का केंद्र होंगे। इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी घटनाएं सामान्य आंखों से देखी जा सकेंगी, यहां तक कि प्रकाश प्रदूषण वाले शहरों में भी।

इन खास घटनाओं के अलावा, हर साल की तरह उल्का वर्षा और रात को तारामंडलों की परेड भी देखने को मिलेगी। हालांकि इन्हें ग्रामीण और अंधेरी जगहों से देखना बेहतर होता है, लेकिन इनमें से कई शहरों से भी दिखाई देंगी। वर्ष की कुछ प्रमुख खगोलीय घटनाओं का विवरण इस प्रकार है।

मार्च, मई और दिसंबर में चंद्रमा की हलचल

मंगलवार, तीन मार्च की शाम को चंद्रग्रहण होगा। इस दौरान पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा और लाल या तांबे जैसे रंग का दिखाई दे सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर चंद्रमा तक पहुंचाता है और यह प्रकाश लाल रंग का होता है, जो दुनिया भर के सूर्योदय और सूर्यास्त की आभा जैसा होता है।

चंद्रग्रहण को सामान्य आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है और यह रात्रि फोटोग्राफी का भी अच्छा अवसर होता है। एक अन्य खगोलीय घटना रविवार, 31 मई को 'ब्लू मून' होगी। यह नाम एक ही कैलेंडर माह में दूसरी पूर्णिमा को दिया जाता है। औसतन यह हर दो-तीन साल में एक बार होता है। चंद्रमा से जुड़ी अंतिम प्रमुख घटना गुरुवार, 24 दिसंबर (क्रिसमस ईव) को 'सुपरमून' होगी। इसमें पूर्णिमा उस समय पड़ती है, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इससे चंद्रमा सामान्य से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा उदय के समय यह प्रभाव सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है, क्योंकि क्षितिज के पास होने पर मस्तिष्क इस आकार को और बड़ा महसूस करता है।

अप्रैल, जून और नवंबर में ग्रहों की हलचल होगी

19 से 22 अप्रैल की सुबह तड़के बुध, मंगल और शनि ग्रह आकाश में एक-दूसरे के काफी करीब दिखाई देंगे। इसके लिए पूर्व दिशा की ओर देखना होगा। मंगलवार, 9 जून और बुधवार, 10 जून की शाम को दो सबसे चमकीले ग्रह शुक्र और बृहस्पति आसमान में एक-दूसरे बेहद करीब दिखाई देंगे। मंगलवार, 3 नवंबर को अर्धचंद्र बृहस्पति के सामने से गुजरेगा। यह घटना दिन में होगी, लेकिन दूरबीन से देखी जा सकेगी। ध्यान रहे, दूरबीन को कभी सूर्य की ओर न करें और बच्चों की पूरी निगरानी करें।

दिसंबर में उल्का वर्षा होगी

दिसंबर के मध्य में सुबह तड़के जेमिनिड उल्का वर्षा देखने का अनुकूल अवसर रहेगा। यह साल की सबसे बेहतरीन उल्का वर्षाओं में से एक मानी जाती है। यह तब होती है जब पृथ्वी 'फेथान' नामक एक पथरीले क्षुद्रग्रह द्वारा छोड़े गए धूल के प्रवाह से गुजरती है। जब ये धूल कण पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जलते हैं, तो प्रकाश की चमकदार लकीरें दिखाई देती हैं, जिन्हें बाकी पेज 8 पर

Jansatta Page

बजट पूर्व उम्मीद | उद्योग निकाय ने घरेलू इस्पात क्षेत्र के लिए बजट पूर्व दिए कुछ सुझाव

हाइड्रोजन तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहन की मांग

नई दिल्ली, 8 जनवरी (भाषा)।

उद्योग निकाय एसोचैम ने सरकार से आगामी बजट में हाइड्रोजन आधारित 'डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन' (डीआरआइ) तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने और इस्पात कंपनियों को इस बदलाव में मदद के लिए रियायती दरों पर हरित वित्त उपलब्ध कराने का आह्वान किया है जिससे स्वच्छ एवं टिकाऊ उत्पादन प्रणालियों में निवेश को बढ़ावा मिल सके।

डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआइ) लोहे के उत्पादन की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें लौह अयस्क (आयरन ओर) को पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस की बजाय कम तापमान पर गैस या हाइड्रोजन की मदद से सीधे लौह में

> *इस्पात* संयंत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित निजी बिजली संयंत्र स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया है जिससे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़े एवं कार्बन उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

बदला जाता है। इससे कार्बन उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2026 को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं। एसोचैम ने घरेलू इस्पात क्षेत्र के लिए कुछ बजट पूर्व सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के तहत 'वेस्ट-हीट रिकवरी सिस्टम' (उद्योगों से निकलने वाली बेकार गर्मी को फिर से ऊर्जा में बदलने वाली प्रणालियों) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इसके अलावा, इस्पात संयंत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित निजी बिजली संयंत्र स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया है जिससे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़े एवं कार्बन उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

उद्योग निकाय ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन कम करना एक चुनौती एवं प्रतिस्पर्धात्मक अवसर दोनों प्रस्तुत करता है और यह दावा किया कि ये उपाय टिकाऊ उत्पादन को गति दे सकते हैं। एसोसिएटेड चेंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम) ने स्क्रैप इकट्ठा करने और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन देने की वकालत करते हुए कहा कि देश की आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कौशल विकास के माध्यम से घरेलू पुनर्चक्रण अवसंरचना को मजबूत करना आवश्यक है। चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उद्योग निकाय ने कहा कि चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक होने और आठ से नौ फीसद की वृद्धि दर बनाए रखने के बावजूद यह क्षेत्र महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है।

प्रमुख कच्चे माल की उच्च लागत, रुपए में गिरावट और घरेलू खनन योग्य भंडार के नगण्य होने के कारण आयातित कोकिंग कोयले पर अत्यधिक निर्भरता प्रमुख समस्याएं बनी हुई है। इसके अलावा, एसोचैम ने कहा कि लौह अयस्क का उत्पादन स्थिर है और नीलाम की गई कई खदानों में अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। इस्पात की बढ़ती मांग तथा लौह अयस्क के निरंतर निर्यात से आपूर्ति पर दबाव पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू मिल के लिए लागत बढ़ रही है। एसोचैम का मानना है कि आगामी केंद्रीय बजट 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत को इस्पात एवं मूल्यवर्धित उत्पादों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

निकाय ने इसे हासिल करने के लिए लौह अयस्क शोधन को बढ़ावा देने, महत्वपूर्ण कच्चे माल पर आयात शुल्क हटाने और दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए 'रायल्टी' गणना को युक्तिसंगत बनाने का आह्वान किया है। एसोचैम ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस्पात पुनर्चक्रण, मिश्र धातु नवाचार तथा प्रक्रिया डिजिटलीकरण में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने से उत्पादकता बढ़ेगी और विशेष इस्पात आयात पर निर्भरता कम होगी।

जागरण विशेष

जीवित कोशिकाएं विकसित कर उपचार पद्धति को दिया नया आयाम

जिस अंग को जरूरत, उसी पर कार्य करेगी नई पद्धति से बनने वाली दवा, विज्ञानी किए गए सम्मानित

विशाल श्रेष्ठ • जागरण

कोलकाता : क्या हो, अगर आईना टूटने पर खुद से जुड़ जाए। टायर अपना पंक्चर खुद ही ठीक कर ले...यानी बेजान चीजों में न सिर्फ जान आ जाए बल्कि वे अपनी समझ से परिस्थिति व जरूरत के मुताबिक काम भी करने लगे। कोलकाता के युवा विज्ञानी डा. दिब्येंदु दास ने अपने विलक्षण वैज्ञानिक ज्ञान से साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लग रही इस चीज को सच कर दिखाया है। उन्होंने न सिर्फ कृत्रिम तरीके से जीवित कोशिकाएं विकसित की हैं, बल्कि उन्हें इंसानों की तरह स्मार्ट भी बना दिया है।

अपने अनूठे शोध से उन्होंने जता दिया है कि देसी प्रयोगशालाओं में भी विश्व स्तरीय शोध संभव हैं और भारत अब सिर्फ वैश्विक तकनीक का उपभोक्ता बनकर नहीं रहने वाला, बल्कि आने वाले समय में मौलिक विज्ञान व डीप टेक के क्षेत्र में नेतृत्व देने को तैयार है। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आइआइएसइआर) कोलकाता में प्रोफेसर 44 वर्षीय डा. दास को उनके विलक्षण शोध के लिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान के क्षेत्र में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया है। कोलकाता के जादवपुर इलाके के रहने वाले दिब्येंदु ने कहा-'एक जीवित कोशिका को तीन चीजों की जरूरत होती है- सुरक्षा के लिए आवरण, ऊर्जा के लिए भोजन व अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन। इसी तरह उनका मरना भी जरूरी है। इसी सिद्धांत पर हमने इसे विकसित करना शुरू किया था। हमने सोचा कि एक छोटे मोलीक्यूल (अणु) से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। यह स्ट्रक्चर तभी तैयार हो सकता है, जब आप उसे भोजन (ऊर्जा) प्रदान करेंगे। इन कोशिकाओं को इस तरह से बनाया है कि इसमें एक ही छोटा मोलीक्यूल रहेगा, जो टूटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसी से जीवित कोशिकाएं विकसित होंगी। 10 वर्षों के गहन शोध के आधार पर हमने अपनी लैब में कृत्रिम तौर पर ऐसी कोशिकाएं विकसित की हैं, जो एटीपी (एडेनोसिन ट्राइफास्फेट) जैसे सक्रिय अणुओं से ऊर्जा लेकर बिल्कुल जीवित कोशिकाओं की तरह काम करती हैं। ये हिल सकती है।अपना आकार बदल सकती हैं और विशेष रासायनिक कार्य कर सकती हैं। डा. दास ने आगे कहा कि मेरा लक्ष्य ऐसी प्रणालियां विकसित करना है, जो बुद्धिमानी से काम करें। इसकी बदौलत ऐसी नैनो-मशीनें बनाई जा सकती हैं, जो इंसानी बाल से हजारों गुना छोटी होंगी और शरीर के अंदर जाकर सीधे लक्ष्य पर काम करेंगी।

चिकित्सा विज्ञान में आ सकती अभिनव क्रांति

डा. दास का शोध भविष्य में ऐसी दवाएं बनाने में बेहद असरदार साबित हो सकता है, जो शरीर के अंदर जाकर सीधे बीमारी वाली जगह पर कार्य करेंगी। मसलन, कैंसर के इलाज के लिए वर्तमान में कीमोथेरेपी जैसी प्रक्रिया शरीर के स्वस्थ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाती है, जबकि इस दृष्टिकोण से विकसित ड्रग डिलीवरी रणनीतियां कैंसर ग्रसित कोशिकाओं को पहचान कर सीधे वहीं अपना प्रभाव छोड़ेंगी, ताकि शरीर के बाकी हिस्से सुरक्षित रहे। कैंसर ही नहीं, आने वाले समय में अन्य असाध्य व गंभीर बीमारियों के इलाज में भी यह शोध रामबाण साबित हो सकता है।

लैब में अपनी टीम के सदस्य के साथ काम करते विज्ञानी डा. दिब्येंदु दास (दाएं) • सौजन्य डा. दिब्येंदु दास

समस्या से मिलेगा समाधान

एमीलोइड्स को अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण माना जाता है, क्योंकि ये मस्तिष्क में प्रोटीन के गुच्छे बना देते हैं, जबकि डा. दास ने अपने शोध से साबित किया है कि इन्हीं एमीलोइड्स संरचनाओं को स्मार्ट बनाकर उनका प्रयोग नैनो-मशीन बनाने में किया जा सकता है। डा. दास का शोध आने वाले समय में ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के बारे में भी बता सकेगा।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

चैटजीपीटी हेल्थ, आपकी सेहत का पूरा डाटा एक जगह

ओपनएआई ने चैटजीपीटी हेल्थ नाम से चैटजीपीटी का एक नया हेल्थ-फीचर लॉन्च किया। इस फीचर के जरिए लोगों को अपनी सेहत को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। आपकी सेहत का पूरा डाटा एक जगह होगा। फिटनेस ऐप भी चैटजीपीटी हेल्थ में जुड़ सकेंगे।

अन्य चैट से अलग होगी हेल्थ की बातचीत

ओपनएआई ने कहा कि यूजर का डाटा सुरक्षित रहेगा। चैटजीपीटी हेल्थ का अलग, सुरक्षित सेक्शन होगा। हेल्थ से जुड़ी चैट बाकी चैट्स से अलग रहेगी। एआई को प्रशिक्षण करने में इस्तेमाल नहीं होगी। खास एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं। आपकी हेल्थ जानकारी आपके नियंत्रण में रहेगी।

यह नया फीचर क्या कर सकता है

- चैटजीपी हेल्थ में आप स्वास्थ्य से जुड़े कई काम कर सकेंगे
- मेडिकल रिकॉर्ड जैसे टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर की जानकारी जोड़ सकते हैं
- वेलनेस और फिटनेस ऐप जोड़ सकते हैं
- आपकी घड़ी, फोन का डाटा जुड़ सकता है

यह डॉक्टर की जगह नहीं लेगा

यह डॉक्टर का विकल्प नहीं है। इसका काम रोजमर्रा के हेल्थ सवाल समझाना। रिपोर्ट्स को समझने में मदद और यूजर को ज्यादा जानकारी और आत्मविश्ववास देना है। अभी यह अमेरिका में लॉन्च हुआ है। लेकिन कुछ महीनों में इसे भारत सहित कई देशों में लॉन्च करने की तैयारी है।

बिना डॉक्टर के चलने वाला एआई क्लीनिक चीन में पहली बार खुला

सोशल मीडिया पर चीन का एक ऐसा क्लीनिक वायरल हो रहा है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस अस्पताल की सबसे चौकाने वाली बात यह है कि यहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, फिर भी मरीज का पूरा इलाज हो जाता है और दवाइयां भी तुरंत मिल जाती है। यह चीन का एआई पावर्ड मेडिकल कियोस्क है, जो दिखने में एक छोटे क्लिनिक है। इसमें घुसते ही मरीज को किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक एआई सिस्टम से बात करनी होती है।

मस्क डाटा सेंटर में करेंगे अधिक निवेश

वॉशिंगटन, एजेंसी। एलन मस्क की एआई कंपनी एक्सआई ने 1,65,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है।

इस भारी भरकम निवेश की मदद से मस्क एआई डाटा सेंटर बनाएंगे। इसके अलावा कुछ हिस्सा ग्रोक चैटबॉट में भी लगाया जाएगा ताकि वह और भी बेहतर तरीके से काम कर सके। आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने को लेकर मस्क का ग्रोक चैटबॉट इन दिनों चर्चा में है। मस्क की कोशिश ओपनएआई के चैटबॉट चैटजीपीटी को कड़ी टक्कर देनी की है। एक्सएआई ने हाल ही में सीरीज ई नाम की फंडिंग राउंड में यह करोड़ों का निवेश हासिल किया।

Hindustan Page

नए सिस्टम से राहगीरों और अन्य वाहनों को उनकी मौजूदगी का संकेत मिल जाएगा

आदेश : अक्तूबर से नई ईवी की आवाज सुनाई देना जरूरी होगा

नई दिल्ली, एजेंसी। इलेक्ट्रिक वाहनों में एक अक्तूबर 2026 से एवीएएस सिस्टम लगाकर देना अनिवार्य होगा। इसकी मदद से बिना आवाज चलने वाली ईवी में ध्वनि पैदा होगी जिससे राहगीरों और साथ चलने वाले वाहनों को उनकी मौजूदगी का संकेत मिल जाएगा।

ऐसा होने से दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर काफी हद तक लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी। यही नहीं एक अक्तूबर 2027 तक पुराने इलेक्ट्रिक वाहन में भी इस अलर्ट सिस्टम को फिट करवाना होगा।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अक्टूबर 2026 से ई-रिक्शा, ई-कार्ट और एम, एम, एल 5 एल 7 श्रेणी के सभी नए इलेक्ट्रिक वाहनों में एवीएएस सिस्टम लगाना अनिवार्य किया है। यह प्रणाली वाहन में आवाज उत्पन्न कर राहगीरों की सुरक्षा बढ़ाता है। मंत्रालय ने सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किए गए मसौदे में अब एल 5 और एल 7 श्रेणी के वाहनों को भी इस नियम में शामिल किया है।

दुनियाभर में इस्तेमाल हो रही तकनीक : इलेक्ट्रिक वाहन धीमी गति में सड़क पर चल रहे राहगीरों के लिए अधिक जोखिम पैदा कर सकते हैं क्योंकि इनमें पारंपरिक इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में राहगीरों के लिए 20 प्रतिशत अधिक और कम गति पर 50 प्रतिशत अधिक जोखिम पैदा करती हैं। यह सिस्टम अमेरिका, जापान और यूरोप में अनिवार्य है, और अब इसे भारत में भी अनिवार्य करने की तैयारी है।

किस श्रेणी में कौन से वाहन

श्रेणी	वाहन
एम	इलेक्ट्रिक कार, बसें
एन	ट्रक और मालवाहक वाहन
एल 5	तीन-पहिया, ऑटो-रिक्शा, मालवाहक वाहन
एल 7	भारी चार-पहिया वाहन

इनमें पहले से ही यह प्रणाली

भारत में कुछ ईवी पहले ही इस सिस्टम के साथ उपलब्ध हैं जिसमें एमजी कॉमेट, टाटा कर्व ईवी/ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसे मॉडल शामिल हैं। महिंद्रा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मॉडल भी इस तकनीक के साथ आते हैं, जो सड़क पर चल रहे लोगों और दो पहिया वालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

क्या है एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम

एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम एक सुरक्षा फीचर है जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों में होता है। इसका काम है पैदल चलने वाले और आसपास के लोगों को यह बताना होता है कि वाहन आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिना आवाज चलते हैं, लोग इन्हें आसानी से सुन नहीं पाते। इसमें लगे स्पीकर के जरिए आवाज निकलती है। यह आवाज वाहन की स्पीड के हिसाब से बदलती है और खासकर कम स्पीड पर या पीछे चलते समय पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाती है।

अन्य प्रस्तावित बदलाव

सरकार ने यह भी प्रस्तावित किया है कि ट्यूबलैस टायर वाले वाहनों, जैसे कार, क्वाड्रिसाइकिल और कुछ थ्री-व्हीलर में स्पेयर टायर की अनिवार्यता को हटा दिया जाए।

12 से 15 हजार जीपीयू खरीदने की तैयारी

आशिष आर्यन
नई दिल्ली, 8 जनवरी

सरकार इंडियाएआई मिशन के तहत एनवीडिया से लगभग 12,000 से 15,000 बी100, बी200 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) लेने के लिए जल्द ही एक और दौर की बोलियां आमंत्रित करेगी। घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'इन नवीनतम तकनीकी जीपीयू के लिए नए एल1 कीमत तलाशने के लिए बोली का एक नया दौर शुरू किया जाएगा। अन्य जीपीयू, जिनके लिए पहले दौर में बोली लगाई गई थी उन्हें पहले दौर की बोली में खोजी गई एल1 कीमत के अनुसार इंडियाएआई मिशन के तहत शामिल किया जाएगा।' बी100 और बी200 एनवीडिया के नवीनतम तकनीकी जीपीयू हैं और यह कंपनी के अत्याधुनिक ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पर बने हैं।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि बी100 और बी200 के अलावा सरकार को उम्मीद है कि कंपनियां बाजार में उपलब्ध अन्य नवीनतम तकनीकी जीपीयू के लिए भी बोली लगाएंगी। एल1 कीमत जीपीयू की आपूर्ति के लिए किसी कंपनी द्वारा लगाई गई सबसे कम बोली है। उदाहरण के लिए इंडियाएआई मिशन के तहत बोली के पहले तीन दौर के बाद खोजी गई औसत एल1 कीमत लगभग 115 रुपये प्रति जीपीयू घंटा थी जबकि एनवीडिया के एच100 जैसी कुछ प्रीमियम जीपीयू के लिए एल1 कीमत लगभग 140 रुपये प्रति जीपीयू घंटा तय की गई थी। (शेष पृष्ठ 2)

इंडियाएआई मिशन

- एनवीडिया के अत्याधुनिक जीपीयू के लिए जल्द बोलियां आमंत्रित करेगी सरकार
- नवीनतम जीपीयू की आपूर्ति के बाद देश में कुल 50,000 से अधिक जीपीयू हो जाएंगे

इसरो 12 जनवरी को लांच करेगा अन्वेषा

नई दिल्ली : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 12 जनवरी को पीएसएलवी-सी62 राकेट के माध्यम से ईओएस-एन1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (अर्थ आब्जर्वेशन सेटेलाइट) लांच करेगा। यह 2026 का पहला मिशन होगा। ईओएस-एन1 (जिसे अन्वेषा भी कहा जाता है) एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे कृषि, शहरी मानचित्रण और पर्यावरण निगरानी में दूरसंवेदी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। (आइएएनएस)

Dainik Jagaran Page

BIHAR

पुनौरा धाम : अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी की टाउन प्लानिंग होगी

- पर्यटन विभाग पूरे इलाके को विकसित करने को लेकर कार्य करेगा
- होटल और यात्री निवास के साथ पर्यटन स्थलों का भी विकास होगा

पटना , हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के सीतामढ़ी में मां जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी की टाउन प्लानिंग की दिशा में काम शुरू होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा नगर विकास विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाई जाएगी।

पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के अनुसार, राज्य सरकार अयोध्या की तरह धार्मिक पर्यटन को प्रमुखता देते हुए सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में नागरिक सुविधाओं का विकास करेगी। इससे सीतामढ़ी सहित उत्तर बिहार में धार्मिक पर्यटन का नया आयाम मिलेगा। उन्होंने बताया कि विभागीय बैठक में पुनौरा धाम विकास योजना की समीक्षा की गई है। पर्यटन विभाग के अनुसार, पुनौरा धाम विकास योजना सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।इसमें 882.87 करोड़ की लागत से भव्य जानकी मंदिर, परिक्रमा पथ, सीता वाटिका और आधुनिक सुविधाओं (थ्री डी शो, पार्किंग, आवास) के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाना शामिल है। इससे यह धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगी। इस राशि में मंदिर के नवीनीकरण के लिए ₹137 करोड़ और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹728 करोड़ शामिल हैं। मंदिर का निर्माण 42 माह में पूरा करने का लक्ष्य है।
पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित होगी

समीक्षा | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक ने बैंकिंग और वेंडर प्रक्रियाओं में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की

नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति बढ़ रही जागरूकता

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को गति देने को लेकर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के निदेशक मीर मोहम्मद अली ने गुरुवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना की प्रगति की समीक्षा की। विद्युत भवन स्थित सभागार में आयोजित इस बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार उपस्थित थे।
बैठक में एमएनआरई निदेशक मीर मोहम्मद ने कहा कि आम उपभोक्ताओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता और भरोसा दोनों मजबूत हो रहे हैं। बैठक के दौरान बैंकिंग और वेंडर प्रक्रियाओं में आ रही चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
एमएनआरई निदेशक ने लोन प्रोसेसिंग में देरी और सब्सिडी की दूसरी किश्त के भुगतान में विलंब जैसी समस्याओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को सौर ऊर्जा से संबंधित सब्सिडी आवेदनों की अस्वीकृति दर को कम करने के निर्देश दिये ताकि उपभोक्ताओं को योजनाओं का पूरा लाभ समय पर मिल सके।

- आपसी समन्वय से इस योजना का क्रियान्वयन करने को कहा

दक्षिण बिहार में 9,885 रूफटॉप सोलर पैनल लगे

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने कहा कि पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना से बिहार में स्वच्छ ऊर्जा का प्रसार तेज हो रहा है एवं उपभोक्ताओं को भी आर्थिक लाभ हो रहा है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने कहा कि दक्षिण बिहार में करीब 9,885 और उत्तर बिहार में 4,715 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इन योजनाओं से न केवल बिजली की लागत में कमी आएगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज होगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य देश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

तकनीक और संचार के क्षेत्र में राज्य नई तस्वीर पेश करेगा : वित्त मंत्री

बजट पूर्व बैठक

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि तकनीक और संचार के क्षेत्र में बिहार पांच वर्षों में विकास की नई तस्वीर पेश करेगा। आगामी बजट में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, तकनीक, संचार एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

अगले पांच सालों में सफलताओं को समेकित कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है, ताकि विकसित बिहार की नई तस्वीर सामने आ सके। श्री यादव ने गुरुवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट पूर्व बैठक में ये बातें कही। यह बैठक दो पाली में आयोजित की गई। पहली पाली में स्वास्थ्य कृषि एवं अन्य विषयों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की गई, जबकि दूसरी पाली में कला-संस्कृति, पर्यटन, वाणिज्य-कर, वानिकी एवं पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण व अन्य विषयों पर प्रतिनिधियों ने विचार रखे। वित्त मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, वित्त के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, वाणिज्य-कर विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में अधिकारी और प्रतिनिधियों ने आगामी बजट को लेकर सुझाव दिए। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में हाईवे, रेल, हवाई अड्डा, तकनीक व उद्योग की स्थापना की वजह से नई अर्थव्यवस्था में पहुंच चुके हैं। भविष्य में नए बिहार का निर्माण और रोजगार की संभावना तैयार करना प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने नगर विकास को निर्देश दिया कि शहर में हुए विकास के अनुसार टैक्स का निर्धारण किया जाए।

पटना के मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में गुरुवार को वित्त विभाग की ओर से बजट पूर्व बैठक करते वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव। साथ में कृषि मंत्री राम कृपाल यादव, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर व सचिव व्यय रचना पाटिल। • हिन्दुस्तान

- वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट पूर्व बैठक की
- कहा, रोजगार की संभावना तैयार करना प्रमुख उद्देश्य
- स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन, खेल, पर्यटन व अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हुए शामिल

कलाकारों के दैनिक मानदेय में बढ़ोतरी की मांग

लोक गायिका रंजना झा व अन्य ने राज्य में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना करने व कलाकारों के दैनिक मानदेय में बढ़ोतरी, पेंशन राशि तीन हजार से बढ़ाने की मांग की। वहीं, बिहा राज्य मोटर ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधियों ने वाहनों के निबंधन के शुल्क में कमी करने सहित अन्य सुझाव दिए।

मेडिकल कॉलेजों में शोध को प्रमुखता मिले

बैठक में मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेजों में उपकरण, भवन मरम्मत, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक करने और शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। आम की खेती करने वाले किसानों की फसल की ब्रांडिग, पान की खेती के लिए पटना में मंडी और आपदा में नुकसान होने पर उचित मुआवजा दिलाने का सुझाव सामने आने पर कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कृषि बाजारों का अत्याधुनिकीकरण, दलहनी और तिलहनी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाने और फल, सब्जी की सुरक्षा के लिए राज्यभर में शीतगृह बनाने व पान आयोग व पान मंडी बनाने का आश्वासन दिया। कहा कि अगले पांच सालों में सब्जी उत्पादन के लक्ष्य को वर्ष में 400 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा।

उद्योग विभाग का बजट बढ़े, सरकारी खरीद में स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाए

- वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मांगों को रखा गया
- चैंबर ने औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, कर सुधार को लेकर दिए कई सुझाव

सुझाव

पटना, वरीय संवाददाता। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से उद्योग, आईटी एवं टैक्सेशन से जुड़े मुद्दों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पूर्व बैठक में विस्तृत सुझाव समर्पित किए गए। इसमें राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, कर सुधार और अवसंरचना विस्तार पर विचार-विमर्श किया गया।

चैंबर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने उद्योग विभाग के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 में उद्योग विभाग का बजट मात्र 1966.26 करोड़ रुपये था, जो कुल बजट का केवल 0.5 प्रतिशत है। इसे 2026-27 में बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए, ताकि औद्योगीकरण की गति को बल मिल सके। उन्होंने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की आवेदन अवधि 31 मार्च 2026 के बाद एक वर्ष तक बढ़ाने की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि बियाडा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ एमएसएमई श्रेणी के सभी उद्यमों को भूमि आवंटन किया जाए। लैंड बैंक की स्थापना, बड़ी परियोजनाओं में सरकार की फेसिलिटेटर की भूमिका और नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास जरूरी है। उन्होंने डोभी के अतिरिक्त गया और कैमूर के बीच कम-से-कम दो नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का सुझाव दिया। उन्होंने 6 प्रतिशत बिजली शुल्क को अत्यधिक बताते हुए इसे घटाने या जीएसटी से समायोजित करने का आग्रह किया। चैंबर ने पर्यटन स्थलों को दर्जा देने, गंगा जलमार्ग से कार्गो परिचालन शुरू करने, स्थानीय उद्योगों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने और लंबित प्रोत्साहन मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग भी की। साथ ही पटना के आसपास आईटी पार्क की स्थापना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंसेंटिव देने, जीएसटी प्रतिपूर्ति के दावों के त्वरित निष्पादन, ई-वे बिल सीमा बढ़ाने तथा पेट्रोल-डीजल व वाहन निबंधन शुल्क को पड़ोसी राज्यों के अनुरूप करने का सुझाव दिया। बैठक में चैंबर के उपाध्यक्ष एनके ठाकुर व विशाल टेकरीवाल, पूर्व अध्यक्ष सुभाष पटवारी, सुनील सराफ, अभिजित वैद और अरुण कुमार उपस्थित रहे।

कार्ययोजना | उत्तर प्रदेश से गंगा नदी का पानी आएगा कर्मनाशा में, 11 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से लाया जाएगा पानी

गंगाजल से अब बुझेगी कर्मनाशा नदी की प्यास

05 सौ 29 करोड़ की योजना तैयार, सिंचाई भी की जा सकेगी

- कर्मनाशा नदी अमूमन सूखी रहती है, जल संसाधन विभाग ने बनायी कार्ययोजना

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। गंगाजल से कर्मनाशा नदी की प्यास बुझायी जाएगी। इसके लिए यूपी से गंगा का पानी कर्मनाशा में लाया जाएगा। लंबी कसरत के बाद इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है।
जल संसाधन विभाग ने इसकी कार्ययोजना बनायी है। जमानियां से ककरैत गंगाजल उद्वह सिंचाई योजना के तहत होने वाले इस कार्य पर 528.44 करोड़ खर्च किये जाएंगे।
अगले 18 माह में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत 11 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से उत्तर प्रदेश से गंगा का पानी बिहार लाया जाएगा। उसे कर्मनाशा नदी में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जमानियां के समीप गंगा नदी पर इनटेक वेल व पंप हाउस का निर्माण होगा। यहां से गंगा नदी का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से बिहार के कैमूर जिला अंतर्गत ककरैत घाट के कर्मनाशा नदी तक लाया जाएगा। इसके जरिए गंगा नदी के पानी का उपयोग विभिन्न उद्वह सिंचाई योजनाओं कर्मनाशा पंप, विश्वकर्मा पंप, लरमा पंप, जैतपुर पंप, तियरा पंप योजना में किया जाएगा।
दरअसल, कर्मनाशा नदी अमूमन सूखी रहती है। पिछले कई वर्षों से कर्मनाशा में प्रायः जल की कमी के कारण कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है। फलस्वरूप किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इनके सामाजिक व आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

योजना में यह होगा

- यूपी के गाजीपुर में जमानियां तहसील के चक्का गांव स्थित चौधरी चरण सिंह पंप हाउस के डाउनस्ट्रीम में 260 मीटर में पंप हाउस संरचना का निर्माण।
- जमानियां स्थित चौधरी चरण सिंह पंप हाउस से यूपी के गाजीपुर एवं चंदौली जिला होते हुए बिहार के कैमूर जिला के ककरैत घाट तक 11 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन का निर्माण।

यह लाभ होगा

इसका सबसे बड़ा लाभ कर्मनाशा नदी को नया जीवन देना है। साल में अधिसंख्य समय पानी संकट से जूझने वाली इस नदी में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। यही नहीं योजना के कार्यान्वयन से कर्मनाशा नदी पर निर्मित कर्मनाशा पंप, विश्वकर्मा पंप के माध्यम से कैमूर जिला के रामगढ़, दुर्गावती एवं नुआंव प्रखंड के 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

चिंता | धारा बदलने और पानी सूख जाने से हजारों एकड़ की खेतीबारी बंद, किसान-मजदूर, जाल बुनकर, नाविक से लेकर बढ़ई तक परेशान, दर्जनों गांवों के लोग पलायन कर रहे

नदियां सिमटीं तो आजीविका के साधन शून्य, खेती-कारोबार भी सिमटा

आएं अपनी नदी बचाएं

मनेर/पटना सिटी, हिटी। नदियों में पानी नहीं होने से खेती,रोजी-रोजगार का पूरा चक्र प्रभावित हो रहा है। नदियां सिमटीं तो इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। किसान, मजदूर, जाल बुनकर, नाविक, बढ़ई सभी की खेती और रोजी-रोटी पर असर पड़ने लगा। बेरोजगारी बढ़ने से लोग शहरों या दूसरे प्रदेश में तेजी से पलायन कर रहे हैं। पटना जिले में गंगा के साथ पुनपुन और सोन नद पर दर्जनों गांव और हजारों की आबादी निर्भर थी।

सोन किनारे परवल, खरबूज-ककड़ी की खेती होती थी : सोन मनेर के हल्दी छपरा के पास गंगा में मिलती है। पानी कम होने से स्थानीय आजीविका पर बड़ा असर हुआ है। सोन नद के किनारे बड़े भू स्थल पर कद्दू, परवल, खरबूज, ककड़ी आदि की खेती बड़े स्तर पर होती थी, लेकिन पानी सूखने से कम हो गई है। यहां बालू मिश्रित मिट्टी होने से फसल खूब होती थी। कोईलवर से लेकर मनेर के हल्दी छपरा तक सोन नद के दोनों किनारे स्थानीय लोग इन फसलों की खेती करते थे, लेकिन नदी की धारा बदलने और सूखने से हजारों एकड़ की खेती बंद हो गई। जमीन वीरान है। किसान कुणाल राय और मजिटर राय कहते हैं कि पहले सोन की दरी (सोन का सपाट भू भाग) बलुआही मिट्टी पर परवल, करेला एवं मटर छेमी की खेती खूब होती थी। नदी किनारे बसा इस्लामगंज मछुआरों का गांव है। पुरुष सदस्य रातभर छोटी-बड़ी नाव से जाल के सहारे मछली मारते थे। इस काम में दो सौ से ज्यादा परिवार शामिल है। मछुआरे भगवान साहनी एवं महावीर सहनी बताते हैं कि हल्दी छपरा संगम के पास सोन और गंगा मिलने के बाद भी सोन की सोती बहती थी। इसमें मछली मारने जाते थे। अब सोती में पानी ही नहीं है। कभी दर्जनों नाव लेकर हल्दी छपरा से लेकर कोईलवर के आगे तक मछली मारने लोग जाते थे और पटना की मंडी में बेचते थे।

सोन नद के हल्दी छपरा घाट पर बेकार पड़ीं नावें। • हिन्दुस्तान

धोबी घाट भी सूखे

शंकर रजक बताते हैं कि तीन-चार पूर्व तक रामपुर के पास सोन में कपड़ा धोने जाते थे, लेकिन सोन में पानी नहीं होने से हमलोगों का धोबी घाट बंद हो गया। अब सब लोग घर पर ही बोरिंग के पानी से कपड़ा धोते हैं।

जाल बनाने का कारोबार घटकर आधा हुआ

बिहार की कई छोटी-बड़ी नदियों के सिमटने और सूखने के कारण जाल का कारोबार प्रभावित हुआ है। कारोबारियो का कहना है कि अब यह व्यापार सिमट कर आधा रह गया है। कारण है कि प्रदेश में बहने वाली कई नदियां या तो सूख चुकी हैं या सिमट गई हैं। इससे जलीय जीव जंतुओं के पकड़ने का कारोबार धीरे-धीरे कम होता गया। नतीजा, जाल के खरीदार भी घटते चले गए। जाल के थोक व्यापारी दामोदर पोद्दार का कहना है कि पहले यहां से दरभंगा, मधुबनी, सासाराम, मोतिहारी समेत सूबे के अधिकतर जिलों के अलावा झारखंड और गोरखपुर से भी लोग जाल खरीदने आते थे। पिछले एक दशक से व्यापारियों के आने का सिलसिला कम होता गया।

मनेर छोड़ बनारस में नाव बना रहे

नाव बनाने वाले कृष्णा महतो कहते हैं अब तो नाव का काम बिल्कुल बन्द है। सोन में पानी रहता था तो नाविक नाव बनवाने या मरम्मत कराने के लिए हमलोगों को ले जाते थे। अब हमलोग बनारस में नाव बनाने का काम कर रहे हैं।

NATIONAL

Hindustan Page

नवाचार उद्यम को लेकर बोले प्रधानमंत्री

भारतीय कृत्रिम मेधा माडल विश्व का नेतृत्व करे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 जनवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत पर दुनिया का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) माडल नैतिक, निष्पक्ष और पारदर्शी होने के साथ-साथ डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित हों। उन्होंने यह भी कहा कि नवाचार को इस देश से वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए और उल्लेख किया कि भारत वहनीय एआइ, समावेशी एआइ और मितव्ययी नवाचार को विश्व स्तर पर बढ़ावा दे सकता है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026' से पहले, भारतीय एआइ स्टार्टअप के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने सुझाव दिया कि भारतीय एआइ माडल विशिष्ट होने चाहिए और उन्हें स्थानीय और स्वदेशी सामग्री तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यमी देश के भविष्य के सह-निर्माता हैं। अगले महीने आयोजित होने वाले 'एआइ फार आलः ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज' शिखर सम्मेलन के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके 12 भारतीय एआइ स्टार्टअप ने बैठक में भाग लिया तथा अपने विचारों और कार्य से अवगत कराया।

बैठक के दौरान, मोदी ने समाज में परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्त्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले महीने 'इंडिया एआइ इम्पैक्ट' शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसके माध्यम से देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एआइ का लाभ उठाकर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है।

'वैश्विक स्तर पर विज्ञान और नवाचार के मामले में तेजी से उभर रहा भारत'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 जनवरी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करंदीकर ने कहा, वैश्विक विज्ञान और नवाचार के लिहाज से भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। भारतीय निवासियों की तरफ से पेटेंट के लिए दाखिल आवेदन के लिहाज से भारत, दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया है।

सचिव ने कहा, भारत अब विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रकाशनों और पीएचडी के मामले में भी वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन देशों में शामिल हो गया है। पिछले एक दशक में वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्थिति में लगातार सुधार के बाद भारत 90 से 30वें स्थान पर पहुंच गया है, जो अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है। सचिव ने इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी (इनसा) के स्थापना दिवस पर बुधवार को कहा, भारत के भावी प्रौद्योगिकी मिशनों पर जोर देते हुए कहा, इसमें राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारतीय भाषाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोग के लिए संप्रभु कृत्रिम मेधा प्रारूप का विकास, बायो-इ3 नीति के तहत बायो-मैन्युफैक्चरिंग पहल शामिल हैं।

पर्यावरणविद् व पश्चिमी घाट संरक्षण के पुरोधा माधव गाडगिल नहीं रहे

मिड-डे, मुंबई

- गाडगिल बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक थे
- पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल को गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है

पश्चिमी घाट संरक्षण के पुरोधा प्रख्यात पर्यावरणविद् माधव गाडगिल का बुधवार देर रात पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। उन्होंने भारत की पारिस्थितिकी अनुसंधान और संरक्षण नीति को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई। गाडगिल बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे।

पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल को गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है। 2024 में, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक जैव विविधता केंद्र पश्चिमी घाट पर उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए गाडगिल को वार्षिक चैंपियंस आफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। उन्होंने भारत के पारिस्थितिक रूप से नाजुक पश्चिमी घाट क्षेत्र पर जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन और विकास गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता की थी। 24 मई,

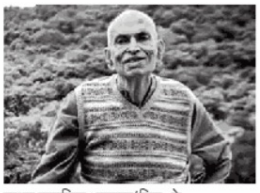

माधव गाडगिल। फाइल/मिड-डे

1942 को पुणे में जन्मे गाडगिल एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक परिवार से थे। उनके पिता, धनंजय रामचंद्र गाडगिल एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और गोखले संस्थान के पूर्व निदेशक थे। माधव गाडगिल ने 1963 में फर्ग्यूसन कालेज से जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1965 में मुंबई विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1969 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने गणितीय पारिस्थितिकी और पशु व्यवहार पर शोध किया।

Dainik Jagaran

आयोजन 53वां विश्व पुस्तक मेला भारतीय सेनाओं को समर्पित, कतर सम्मानित अतिथि देश

भारत मंडपम में कल से सजेगा पुस्तकों का मेला, प्रवेश निशुल्क

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 जनवरी।

भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी तक 53वां विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष मेले का समर्पण भारतीय सशस्त्र सेनाओं को किया गया है और पहली बार प्रवेश पूरी तरह से निशुल्क रहेगा। मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। कतर और स्पेन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित रहेंगे।

नौ दिवसीय पुस्तक मेला का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) के अनुसार, इस बार मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक 3000 से ज्यादा स्टाल के साथ भाग लेंगे। मेले में 600 से अधिक सत्र होंगे, जिसमें 1000 से अधिक वक्ता हिस्सा लेंगे। एनबीटी अध्यक्ष मिलिंद सुधाकर मराठे ने बताया कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साहस, बलिदान और योगदान को समर्पित 1,000 वर्ग मीटर का थीम पवेलियन तैयार किया गया है।

'पुस्तकें ज्ञान के माध्यम के साथ मानवीय समझ बढ़ाने का भी जरिया'

इस वर्ष कतर को सम्मानित अतिथि देश और स्पेन को फोकस देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत में कतर के राजदूत मोहम्मद हसन जाबिर अल जाबेर ने मेले को 'दुनिया के प्रमुख सांस्कृतिक मंचों में से एक' बताते हुए कहा कि पुस्तकें ज्ञान का माध्यम होने के साथ मानवीय समझ बढ़ाने का भी जरिया हैं। वहीं, मेला भारतीय भाषाओं के प्रकाशक, अंतरराष्ट्रीय पवेलियन्स, बाल मंडपम, आथर्स कार्नर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से विभाजित किया गया है। एम्फीथिएटर- कर्म सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित होंगी।

ये होगा आकर्षण

मुख्य आकर्षण में अर्जुन टैंक, आइएनएस विक्रांत और एलसीए तेजस की प्रतिकृतियां, 21 परमवीर चक्र विजेताओं को श्रद्धांजलि और 1947 से लेकर आपरेशन सिंदूर तक प्रमुख युद्धों पर सत्र शामिल हैं। इसके अलावा वंदे मातरम् और सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी।

इसमें 500 से अधिक पुस्तकें, पोस्टर, डाक्यूमेंट्री और इंस्टालेशन प्रदर्शित किए जाएंगे।

Jansatta Page

सुप्रीम सवाल

राज्यसभा के उपसभापति क्यों नहीं कर सकते सभापति के कार्य

शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की ओर से कार्य करने का दिया हवाला, महाभियोग मामले में जांच समिति को चुनौती देने वाली जस्टिस वर्मा की याचिका पर बहस पूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कदाचार के आरोपों में महाभियोग प्रक्रिया का सामना कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच समिति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य कर सकते हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति सभापति के कार्य क्यों नहीं कर सकते? कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब जस्टिस वर्मा के वकील दलील दे रहे थे कि राज्यसभा के उपसभापति के पास प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के तहत सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को ही किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और एससी शर्मा की पीठ ने गुरुवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली। इसके अलावा जस्टिस वर्मा को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लगा है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने जांच समिति के समक्ष जवाब देने के लिए तय 12 जनवरी की तारीख बढ़ाने का उनकी ओर से किया गया अनुरोध नहीं माना।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा जब दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, तब गत 14 मार्च की रात उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग लग गई थी। आग बुझाने पहुंचे अग्निशमन दल को आवास के एक स्टोर रूम में भारी मात्रा में जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं। इस मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ कदाचार में पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग की कार्यवाही लंबित है। लोकसभा सांसदों के महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार करते हुए जांच कमेटी गठित की है। इसके समक्ष जस्टिस वर्मा को 12 जनवरी तक जवाब देना है।

12 जनवरी को जांच समिति के समक्ष जवाब दाखिल करने की समय बढ़ाने भी किया इन्कार

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

जस्टिस वर्मा के वकीलों ने दिया अनुच्छेद 91 के प्रविधानों का हवाला

गुरुवार को जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की। रोहतगी और लूथरा की दलीलें थीं कि राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा सदस्यों द्वारा दिया गया प्रस्ताव खारिज करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 91 के प्रविधान लागू नहीं होंगे, जो राज्यसभा के उपसभापति को सभापति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वाहन करने की अनुमति देता है। उनका कहना था कि न्यायाधीश जांच अधिनियम में जो अधिकार सभापति को दिए गए हैं, उपसभापति उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जब तक नए सभापति का चुनाव होता, तब तक मामले में इंतजार किया जाना चाहिए था। ज्ञातव्य हो कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा देने के बाद उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा सदस्यों द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग कार्यवाही शुरू करने का दिया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया था। हालांकि, लोकसभा सदस्यों द्वारा दिया गया प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था और एक जांच समिति का भी गठन कर दिया।

आधार वर्ष में बदलाव से एनएसओ अनुमान से ज्यादा रहेगी जीडीपी

नई दिल्ली, एनएआइ: आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए नया आधार वर्ष जारी करने के बाद जीडीपी वृद्धि दर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मौजूदा अनुमान से ज्यादा रह सकती है। स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआइ) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनएसओ द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान में चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.4% रहने की बात कही है। जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान यह 6.5% थी। मौजूदा कीमतों पर जीडीपी आठ प्रतिशत रहने का अनुमान है।

एसबीआइ का मानना है कि आधार वर्ष 2022-23 करने के बाद चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.5% रह सकती है और इसमें ऊपर की तरफ संशोधन हो सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दूसरा अग्रिम अनुमान 27 फरवरी को जारी होगा और आधार वर्ष बदलने के बाद वृद्धि दर में ऊपर की संशोधन होगा। एसबीआइ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐतिहासिक तौर पर आरबीआइ और एनएसओ के जीडीपी वृद्धि अनुमानों के बीच का अंतर आमतौर पर 20-30 आधार अंक के बीच में रहा है और इसलिए चालू वित्त वर्ष के लिए 7.4% वृद्धि दर के अनुमान को ठीक और उम्मीद के मुताबिक है।

एसबीआइ ने कहा-बेस ईयर 2022-23 करने से चालू वित्त वर्ष में 7.5% हो सकती है वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी

2026 में 6.6% रहेगी भारत की जीडीपी

नई दिल्ली, आइएएनएस: संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 2026 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता से वैश्विक वृद्धि दर घटकर 2.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मजबूत मांग भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के असर को कुछ कम कर सकती है।

संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले 7.4% से कम कर दिया है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुमान के मुताबिक। आइएमएफ भारत को एकमात्र सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर देखता है। उसने 2025-26 में छह प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यूएन ने अपनी 'विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026' रिपोर्ट में कहा है कि दुनियाभर की अर्थव्यवस्था को महामारी से पहले के समय की तुलना में लंबे समय तक धीमी वृद्धि का खतरा है, क्योंकि मौजूदा वृद्धि दर बड़े पैमाने पर विकास संबंधी लाभ देने में नाकाम रही है, जिससे कई देश, समुदाय और परिवार पीछे रह गए हैं। भू-राजनीतिक तनाव, नीतिगत अनिश्चितता और राजकोषीय चुनौतियों ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को धुंधला कर दिया है। 2026 में वैश्विक वृद्धि नरम पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि कमजोर वैश्विक व्यापार को मौद्रिक मदद से कुछ हद तक ही संभाला जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्यादातर इकोनमी में महंगाई कम हुई है फिर भी रहने का बढ़ता खर्च घरेलू बजट पर दबाव डाल रहा है और असमानता को बढ़ा रहा है।

UNITED NATIONS

- संयुक्त राष्ट्र ने कहा- मजबूत मांग भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के असर को कुछ हद तक करेगी कम
- नीतिगत अनिश्चितता के चलते वैश्विक वृद्धि दर घटकर 2.7 प्रतिशत रहने के आसार

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, तैयारियां तेज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 जनवरी।

संसद का आगामी बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। इस सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार रविवार (एक फरवरी) को अपना बजट पेश करेगी। इस बजट की तैयारियां केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। यह तीसरी भाजपा सरकार का को दूसरा पूर्ण बजट होगा। यह सत्र दो चरण में होगा। बजट की तैयारियों को लेकर संबंधित मंत्रालयों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और हाल ही में खुद वित्त मंत्री ने बजट से संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी और बजट पर उनके सुझाव भी लिए थे।

इस बजट सत्र में ही केंद्र सरकार 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण रपट भी पेश करेगी। जिसमें देश की मौजूदा स्थिति का लेखा जोखा पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार लगातार देश में विभिन्न योजनाओं को विशेष कार्य योजना के तहत पूर्ण करने की तैयारियां कर रही है, जिसके तहत भविष्य की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की जा रही है। देश की इन भविष्य की कार्य योजनाओं को इस बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। इस बजट में गौर करने वाली बात यह भी है कि यह बजट रविवार को 28 फरवरी पेश होगा। इससे पहले कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में सामान्यतौर प र बजट 28 फरवरी को ही पेश होता था लेकिन भाजपा सरकार ने बदलाव किया था। बताया जा रहा है कि इस सत्र शुरुआत 28 फरवरी को राष्ट्रपति को अभिभाषण सत्र से शुरू होगी। सत्र का पहला हिस्सा 28 से 13 फरवरी तक चलेगा ओर दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होकर दो अप्रैल तक चलेगा।

> *यह* सत्र दो चरण में होगा। बजट की तैयारियों को लेकर संबंधित मंत्रालयों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है।

भारत की दस साल की पदक रणनीति का अनावरण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 जनवरी।

सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीकृत महत्वाकांक्षी पदक रणनीति का अनावरण शुक्रवार को अहमदाबाद में आयोजित खेल प्रशासन सम्मेलन में खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस रणनीति का लक्ष्य अगले दस वर्षों में भारत को दुनिया के शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल करने का है।

खेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने इस योजना को देखा और स्वीकृति प्रदान की है, जो खेलों में दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है। सम्मेलन में खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के बीच समन्वय को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 ओलंपिक की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की तैयारियों की समग्र समीक्षा की जाएगी।

महासंघों को अपनी अतिरिक्त जिम्मेदारियां समझाने और खिलाड़ी-केंद्रित सुधारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अल्पकालिक टूर्नामेंट-आधारित रणनीतियों से हटकर दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अहमदाबाद का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यह 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान शहर है और 2036 ओलंपिक की दावेदारी भी कर रहा है। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि सम्मेलन भारत के दीर्घकालिक खेल रोडमैप और प्राथमिकताओं पर साझा समझ विकसित करेगा।

वित्त वर्ष 27 में राजकोषीय घाटा बढ़ेगा!

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 8 जनवरी

सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2026-27 (वित्त वर्ष 27) में 4.6 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। हालांकि अनुमान यह है कि सरकार आगामी बजट में यह लक्ष्य 4.3 प्रतिशत घोषित कर सकती है। फिच सॉल्यूशंस की इकाई बीएमआई की गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़ने के कारक नए खर्चों की जरूरत और कम कर की प्राप्ति हो सकती है।

बीएमआई के मुताबिक सरकार के अधिक राजस्व अर्जित कर पाती है तो नए खर्च से सार्वजनिक घाटे में वृद्धि होना जरूरी नहीं है। हालांकि 2025 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और आयकर सुधारों के कारण कर राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया कि आगामी केंद्रीय बजट में सीमा शुल्क के युक्तिकरण से कर राजस्व में और कमी आएगी।

बीएमआई के अनुसार भारत को खतरनाक बाहरी वातावरण के कारण नए खर्चों के साथ रक्षा पर खर्च बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन केंद्रीय सरकार का के व्यय में स्थिरता आ गई है और यह 2018-2000 के बाद महत्त्वपूर्ण रूप से कम हो गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, 'चीन ने रक्षा पर खर्च बढ़ा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में भारत के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में सुरक्षा पर खर्च बढ़ाना अनिवार्य है।' रिपोर्ट के अनुसार सरकार को वित्त वर्ष 27 के लिए बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3 प्रतिशत तय करना पड़ सकता है ताकि आर्थिक गतिविधियां पर प्रभाव को न्यूनतम कर मध्यम अवधि के ऋण लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। विकसित भारत के विजन के मुताबिक आधारभूत ढांचे और लघु से लेकर मध्यम आकार के उद्यमों को मदद करने की आवश्यकता है।

वित्त वर्ष 27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% तय करना पड़ सकता है ताकि मध्यम अवधि के ऋण लक्ष्य हासिल हो सकें

गणतंत्र दिवस की झांकी में दिखेगी पिंक बस, अनुसूचित जाति की बेटी संभालेगी स्टेयरिंग

जागरण संवाददाता, पटना: इस वर्ष 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में बिहार की महिला सशक्तीकरण की अनूठी झलक देखने को मिलेगी। पहली बार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की पिंक बस को झांकी में शामिल किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस पिंक बस की स्टेयरिंग अनुसूचित जाति समुदाय की एक बेटी के हाथों में होगी, जो आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता का मजबूत संदेश देगी। झांकी की तैयारी को लेकर इन दिनों बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पटना स्थित कार्यालय परिसर में नियमित रूप से अभ्यास चल रहा है। चयनित चालक को झांकी के दौरान बस संचालन, गति नियंत्रण और निर्धारित मार्ग पर अनुशासित ढंग से चलने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार गणतंत्र दिवस पर पिंक बस को विशेष रूप से सजाया जाएगा, ताकि महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण का संदेश प्रभावी रूप से देशभर तक पहुंचे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल वर्मा ने बताया कि गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान झांकी में इसबार पिंक बस भी प्रदर्शित की जाएगी।

- **झांकी की तैयारी को लेकर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यालय परिसर में नियमित रूप से अभ्यास चल रहा**
- **राज्य में वर्तमान में कुल 100 पिंक बसें संचालित हो रही हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं के उद्देश्य को पूरा कर रही**

गौरतलब है कि बिहार में वर्तमान में कुल 100 पिंक बसें संचालित हो रही हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। इन बसों में महिला कंडक्टरों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा से जुड़े अन्य इंतजाम किए गए हैं। पिंक बस सेवा को महिलाओं से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

गणतंत्र दिवस की झांकी में पिंक बस की भागीदारी न केवल परिवहन उपलब्धि को दर्शाएगी, बल्कि यह संदेश भी देगी कि बिहार में सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। यह झांकी राज्य की प्रगतिशील सोच और समावेशी विकास की पहचान बनेगी।

पिंक बस में महिला यात्रियों को कई सुविधाएं दी गई हैं। ● जागरण

भारत में चीन की कंपनियां भी ले सकेंगी ठेके

नई दिल्ली, रायटर : भारत और अमेरिका में बढ़ती तनातनी के बीच नई दिल्ली ने चीन की कंपनियों के लिए अपना दरवाजा खोलने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय वित्त मंत्रालय सरकारी ठेकों के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों पर लगे पांच साल पुराने प्रतिबंधों को हटाने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि भारत-चीन सीमा पर जिस तरह तनाव कम हो रहा है, उसे देखते हुए भारत सरकार व्यापारिक संबंधों को तेजी से पटरी पर लाना चाहती है।

2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके तहत चीनी कंपनियों को बोली लगाने के लिए भारतीय सरकारी समिति के साथ रजिस्ट्रेशन कराना और राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था। इन उपायों के चलते चीनी कंपनियों को भारत सरकार के उन ठेकों के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया गया था, जिनकी अनुमानित लागत 700 अरब डालर से 750 अरब डालर के बीच थी।

- **चीनी कंपनियों पर लगे पांच साल पुराने प्रतिबंध को हटाने की तैयारी में भारत**
- **सीमा पर तनाव घटने से तेजी से पटरी पर आ रहे भारत और चीन के संबंध**

सूत्रों ने बताया कि अधिकारी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है। प्रेटू के अनुसार, गुरुवार को मशीनरी और उपकरण बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें बीएचईएल के शेयर 10 प्रतिशत से अधिक गिर गए। यह गिरावट उन रिपोर्टों के बीच आई है कि वित्त मंत्रालय सरकारी ठेकों के लिए चीनी कंपनियों की बोली पर प्रतिबंध हटाने की योजना बना रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने का डर पैदा हो गया है। हिताची एनर्जी इंडिया के शेयर 5.88 प्रतिशत और एबीबी इंडिया के शेयर 4.86 प्रतिशत तक गिर गए। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला अन्य सरकारी विभागों के अनुरोधों के बाद किया है।

आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए शुभंकर 'उदय' लांच

नई दिल्ली, एजेंसी: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने गुरुवार को आधार का शुभंकर (प्रतीक चिह्न) लांच किया, जो लोगों को आधार सेवाओं की सरल जानकारी देने के लिए सुलभ संचार माध्यम है। उदय नामक यह शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी अधिक सहज और सुलभ बनाने में सहायक होगा।

शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता में केरल के त्रिशूर के अरुण गोकुल प्रथम विजेता रहे, जबकि महाराष्ट्र के पुणे के इदरीस दबाईवाला को द्वितीय पुरस्कार और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी कृष्णा शर्मा को तीसरा पुरस्कार मिला। वहीं, भोपाल की रिया जैन ने शुभंकर नामकरण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि पुणे के इदरीस दबाईवाला दूसरे और हैदराबाद के महाराज सरन चेल्लापिल्ला तीसरे स्थान पर रहे।

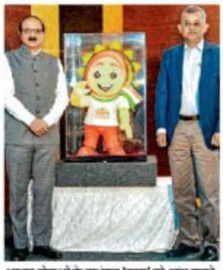

आधार सेवाओं के शुभंकर 'उदय' को लांच करते यूआइडीएआइ के सीईओ भुवनेश कुमार और चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा (दाएं)। प्रेटू

यूआइडीएआइ के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा ने तिरुअनंतपुरम में आयोजित समारोह में शुभंकर जारी किया।

इस वर्ष 52 बड़े सुधार करेगा भारतीय रेलवे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए अत्यधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद बनने की दिशा में तेज कदम बढ़ा रहा है। नए साल में सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर होगी। इसी सिलसिले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को रेल भवन में राज्य मंत्रियों एवं शीर्ष अधिकारियों के साथ विमर्श किया। इसमें चालू वर्ष के 52 सप्ताह में 52 बड़े सुधार का संकल्प लिया गया, यानी हर सप्ताह एक ठोस सुधार लागू करने का लक्ष्य। इसका सीधा फायदा रेल यात्रियों को मिलेगा। इससे काम करने की रफ्तार बढ़ेगी, व्यवस्था पारदर्शी होगी और सेवाएं समय पर मिलेंगी।

रेलवे में सुरक्षा को लेकर बीते वर्षों में बड़ा सुधार हुआ है। वर्ष 2014-15 में जहां गंभीर रेल दुर्घटनाओं की संख्या 135 थी, वह 2025-26 में घटकर सिर्फ 11 रह गई है। यह लगभग 90 प्रतिशत की कमी है। रेलवे के पास एक बड़ी शिकायत खान-पान को लेकर भी आती है। अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता, कैटरिंग और ट्रेन में मिलने वाली अन्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े सुधारों का फैसला लिया है। इसका सीधा लाभ लंबी दूरी के यात्रियों को मिलेगा। बैठक में अधिकारियों ने अपने क्षेत्र के अनुभव साझा किए।

- **यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को दी जाएगी सर्वोच्च प्राथमिकता**

अश्विनी वैष्णव। फाइल

रेलवे के 100 अधिकारियों व कर्मियों को आज मिलेगा अति विशिष्ट सेवा सम्मान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में शुक्रवार को 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2025 समारोह में रेलवे के सौ अधिकारियों-कर्मचारियों को असाधारण योगदान के लिए सम्मानित करेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोनों को 26 शील्ड भी प्रदान की जाएंगी। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए उन कर्मियों का चयन किया गया है, जिन्होंने नवाचार, परिचालन दक्षता, सुरक्षा, संरक्षा, राजस्व वृद्धि, समयबद्ध परियोजना पूर्णता, खेल और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनमें 17 अधिकारी-कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने नए विचार और तकनीकें अपनाकर उत्पादकता बढ़ाई।

एनसीईआरटी को इस महीने के मिल जाएगा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **यूजीसी ने पूरी की तैयारियां, बोर्ड की मंजूरी मिलते ही जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन**
- **स्कूलों से जुड़ी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के साथ ही शोध विश्वविद्यालय के रूप में करेगा काम**

स्कूली बच्चों के लिए शोधपरक व सस्ती पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) अब जल्द ही एक शोध विश्वविद्यालय के रूप में काम करते हुए दिखेगा। जहां छात्रों को रिसर्च आधारित कुछ नए डिग्री कोर्स पढ़ने को मिल सकते हैं। इनमें बीए व बीएससी विद रिसर्च जैसे कोर्स शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय की सहमति के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे लेकर अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जो संकेत मिल रहे हैं, उनमें इस महीने के अंत तक होने वाली यूजीसी बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा।

एनसीईआरटी के शिक्षा व शोध क्षेत्र से जुड़े लंबे अनुभव को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2023 में ही इसको विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील करने का एलान किया था। तभी से इसके विश्वविद्यालय बनाने की पहल शुरू हुई थी। सूत्रों की मानें तो इसके स्वरूप व कामकाज के तरीके को लेकर चले लंबे मंथन के बाद आखिरकार इसको पूर्व की जिम्मेदारियों के साथ इसके अनुभव से नई पीढ़ी को जोड़ने को लेकर सहमति दी गई। जिसमें वह शोध आधारित नए डिग्री व पीएचडी जैसे कोर्सों को शुरू कर सकता है। एनसीईआरटी का गठन 1961 में किया गया था। तब से वह स्कूली पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने व प्रशिक्षण का काम कर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, इस दर्जे के बाद एनसीईआरटी का पहले की तरह केंद्रीय संस्थान का स्वरूप बरकरार रहेगा। साथ ही शिक्षा मंत्रालय से मिलने वाली वित्तीय मदद भी जारी रहेगी। वहीं विश्वविद्यालय का दर्जा मिलते ही उसकी स्वायत्तता बढ़ जाएगी। इस पहल को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की उस पहल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता देने की सिफारिश की गई है।

INTERNATIONAL

अमेरिका साठ से अधिक वैश्विक संस्थाओं से बाहर

संयुक्त राष्ट्र निकायों व अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से भी अलगाव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 जनवरी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों और भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइएसए) समेत 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का फैसला किया है। ट्रंप ने इन संस्थाओं को अनावश्यक और अमेरिका के हितों के विरुद्ध बताया।

ट्रंप ने बुधवार को 'संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से अमेरिका को बाहर निकालना' शीर्षक वाले एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों का सदस्य बने रहना, उनमें भागीदारी करना या किसी भी रूप में उन्हें समर्थन देना अमेरिका के हितों के विपरीत है।

वाइट हाउस द्वारा बुधवार को जारी एक पत्र के अनुसार, इनमें 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय और 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि या संप्रभुता के विरुद्ध कार्य करते हैं। ट्रंप ने सभी कार्यकारी विभागों और एजंसियों को निर्देश दिया कि वे इन संगठनों से अमेरिका की वापसी को यथाशीघ्र लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र निकायों के मामले में, कानून द्वारा अनुमेय सीमा तक, इन संस्थाओं में भागीदारी या वित्तपोषण समाप्त करना ही वापसी माना जाएगा। जिन संगठनों से अमेरिका अलग हो रहा है, उनमें जलवायु परिवर्तन पर भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भी शामिल है। वर्तमान में आईएसए के 100 से अधिक देश हस्ताक्षरकर्ता हैं और 90 से अधिक देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए इसकी पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा जिन संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी पूरी सूची उन्हें प्राप्त हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्ट्ज ने 'एक्स' पर कहा कि अमेरिका अब उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों को न तो वित्तपोषित करेगा और न ही उनमें भागीदारी करेगा, जो अमेरिकी हितों को पूरा नहीं करते या कई मामलों में उनके विरुद्ध हैं।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने इन 66 संस्थानों को अपने दायरे में अनावश्यक, कुप्रबंधित, अपव्ययी, खराब ढंग से संचालित, अपने एजंडे को आगे बढ़ाने वाले तत्वों के कब्जे में या देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और समग्र समृद्धि के लिए खतरा पाया है।

हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों का सदस्य बने रहना, उनमें भागीदारी करना या किसी भी रूप में उन्हें समर्थन देना अमेरिका के हितों के विपरीत है।

'अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 125 देशों के साथ काम जारी रखेगा'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 जनवरी।

भारत के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइएसए) अपने 125 सदस्य देशों के साथ मिलकर सौर ऊर्जा के माध्यम से जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयास जारी रखेगा। अमेरिका के इस गठबंधन से बाहर निकलने के बाद आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

आइएसए का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। यह भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को एकजुट करना है। इसे 2015 में पेरिस में सीओपी21 सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। भारत सरकार ने मीडिया की खबरों को देखा है, जिनमें 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जिनमें आइएसए भी शामिल है, से अमेरिका के बाहर निकलने का जिक्र किया गया है।' यह गठबंधन सदस्य देशों के साथ काम करना जारी रखेगा। खासकर विकसित देशों व छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के साथ, सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग, वित्तीय संसाधनों के जुटाने, क्षमता निर्माण और जोखिम की धारणा को कम करने में सहयोग किया जा सके। भारत इस गठबंधन का अध्यक्ष देश है, जिसमें अब 125 सदस्य और संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश शामिल हैं।

बांग्लादेश ने भारत में वीजा सेवा निलंबित की

ढाका, प्रेट्र : भारत से चल रही तनातनी के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए दिल्ली सहित भारत में स्थित अपने प्रमुख मिशनों से वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। विदेश मामलों के सलाहकार एम.तौहीद हुसैन ने अपने कार्यालय में एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि बांग्लादेश ने अमेरिका द्वारा हाल में लागू की गई 'वीजा बांड' की जरूरत से भी रियायत की मांग की है हुसैन ने कहा- 'मैंने भारत में स्थित अपने तीनों मिशनों को फिलहाल वीजा सेक्शन बंद रखने के लिए कहा है। यह सुरक्षा का मामला है।' सलाहकार की यह टिप्पणी तब आई जब कोलकाता स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायोग ने रातोंरात वीजा सेवाओं को बंद कर दिया जबकि दिल्ली और अगरतला में भी इसी तरह के कदम उठाए गए थे।

अमेरिका के रक्षा बजट में 600 अरब डालर की वृद्धि करेंगे ट्रंप

2027 के लिए 1500 अरब डालर के बजट का रखा प्रस्ताव

न्यूयार्क टाइम्स से

2026 के लिए 901 अरब डालर के बजट को मिली है मंजूरी

वाशिंगटन: वेनेजुएला पर अप्रत्याशित हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की दुनिया में धाक बढ़ाने में जुट गए हैं। इस कवायद में वह सैन्य खर्च में 600 अरब डालर की भारी वृद्धि करने जा रहे हैं। उन्होंने 2027 के लिए 1500 अरब डालर के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है। यह मौजूदा रक्षा बजट के मुकाबले करीब डेढ़ गुना से भी ज्यादा है। अमेरिकी संसद ने 2026 के लिए 901 अरब डालर के रक्षा बजट को मंजूरी दी है। उनके इस कदम को वेनेजुएला और उसके बाहर अमेरिकी साम्राज्य को बढ़ावा देने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

ट्रंप ने बुधवार को अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, 'हमारा सैन्य बजट वर्ष 2027 के लिए एक ट्रिलियन डालर (एक हजार अरब डालर) नहीं बल्कि 1.5 ट्रिलियन डालर होना चाहिए। इससे हम ऐसी सेना खड़ी कर सकेंगे, जिससे हम लंबे समय तक खुद को सुरक्षित रख सकेंगे, चाहे दुश्मन कोई भी हो।' अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा से किन हथियार कार्यक्रमों और सैन्य इकाइयों को लाभ होगा।

हालांकि सैन्य खर्च में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। संसद के दोनों सदनों में रिपब्लिकन को मामूली बहुमत है।

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

चीन से चार गुना तो भारत से दस गुना अधिक बजट

चीन का अभी रक्षा बजट 245 अरब डालर है, जो दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बजट है। जबकि भारत का रक्षा बजट 81 अरब डालर से ज्यादा है। इस लिहाज से अमेरिका का रक्षा बजट चीन के मुकाबले चार गुना तो भारत की तुलना में दस गुना से भी ज्यादा है।

दुनिया में सैन्य शक्ति प्रदर्शन के बीच की यह घोषणा

राष्ट्रपति ने सैन्य खर्च में 600 अरब डालर की वृद्धि की मांग ऐसे समय की है, जब उनका प्रशासन दुनिया भर में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। पिछले सप्ताह अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक अप्रत्याशित सैन्य अभियान चलाया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिका लाया गया। इसके बाद ट्रंप ने डेनमार्क के नियंत्रण वाले ग्रीनलैंड को बलपूर्वक अमेरिका के कब्जे में लेने की धमकी दी।

आठ युद्ध खत्म किए, नार्वे ने नासमझी में नोबेल नहीं दिया

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने आठ युद्ध खत्म कराए हैं। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार मायने नहीं रखता, पर उन्हें लगता है कि नार्वे, जो नोबेल शांति पुरस्कार समारोह की मेजबानी करता है, ने उन्हें यह पुरस्कार नासमझी के कारण नहीं दिया। अपनी विदेश नीति को अमेरिकी मिलिट्री पावर से जोड़ते हुए कहा, उनके नेतृत्व में अमेरिकी ताकत ने ग्लोबल डेटरेंस को बहाल किया और दुश्मनों से सम्मान हासिल किया। "चीन व रूस जिस एकमात्र देश से डरते और सम्मान करते हैं, वह फिर से बनाया गया अमेरिका है। नाटो में सहयोगी देशों की आलोचना करते हुए कहा, कई सदस्य देश तब तक रक्षा खर्च की जिम्मेदारियों पूरा करने में नाकाम रहे, जब तक उन पर दबाव नहीं डाला। अमेरिका वर्षों से बेवकूफी से उनके लिए पैसे दे रहा था। कहा कि अगर वह शामिल नहीं होते, तो रूस के पास अभी पूरा यूक्रेन होता। अमेरिका के बिना रूस व चीन को नाटो का बिल्कुल भी डर नहीं है।"

कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो के फोन पर ट्रंप से सुर बदले, व्हाइट हाउस बुलाया

- ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, पेट्रो की फोन काल, उनका लहजा पसंद आया
- रविवार को पेट्रो को बताया था कोकेन तस्करी करने वाला बीमार आदमी

बोगोटा, रायटर: अमेरिका के साथ बढ़ी तनातनी के बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। ट्रंप ने इस बातचीत की काफी प्रशंसा की और कहा, पेट्रो का फोन और उनका लहजा काफी पसंद आया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, पेट्रो को व्हाइट हाउस में आमंत्रित भी किया गया है। हालांकिये नहीं बताया कि भेंट कब होगी। ज्ञात हो, ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई के तहत ट्रंप ने रविवार को कोलंबिया पर सैन्य कार्रवाई की मंशा जताई थी। वहीं वेनेजुएला का समर्थन करते हुए पेट्रो ने सुरक्षा परिषद की बैठक प्रस्तावित की थी। ये भी एलान किया था कि जरूरत पड़ी तो वह अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाएंगे। अमेरिका-कोलंबिया ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान में गत 30 वर्षों से साझेदार हैं, पर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों के बीच तनाव बढ़ा है। पेट्रो ने एक जनसभा में कहा, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे पहली बार फोन पर बात हुई। गतिरोध व असहमतियों पर चर्चा हुई। वहीं पेट्रो ने राजधानी में कोलंबिया की संप्रभुता का जश्न मनाने को -जुटे लोगों से कहा, ट्रंप से दोनों देशों के बीच पुनः वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है।

कोलंबिया में बुधवार को जनसभा को संबोधित करते राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। रायटर

Dainik Jagaran

भारत पर 500% शुल्क का जोखिम!

रूस से तेल खरीदने वालों पर 'दंड' लगाने वाले विधेयक को ट्रंप का समर्थन

श्रेया नंदी
नई दिल्ली, 8 जनवरी

भारत को रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका के द्वितीयक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें रूस से तेल की खरीद पर 500 फीसदी तक का दंडात्मक शुल्क भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को 'दंड' देने के उद्देश्य से इस तरह के एक विधेयक का समर्थन किया है।

अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने द्विदलीय रूस प्रतिबंध विधेयक को 'हरी झंडी' दे दी है जिसका उद्देश्य रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को निशाना बनाना है। प्रस्तावित उपाय 'सैंक्शनिंग रशिया ऐक्ट 2025' का हिस्सा है। यदि इस विधेयक को मंजूरी मिलती है तो इसके बाद बना कानून मामलों को जटिल बना सकता है और भारत तथा अमेरिका के बीच नौ महीनों से चल रहे व्यापार समझौते की संभावनाओं को खतरे में डाल सकता है।

ग्राहम ने एक बयान में कहा, 'यह विधेयक राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को दंडित करने की अनुमति देगा जो सस्ते रूसी तेल खरीदकर रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के युद्ध मशीन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह विधेयक ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर जबरदस्त दबाव बनाने में सक्षम करेगा और उन्हें सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।'

विधेयक के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद में जानबूझकर शामिल होने वाले देशों की वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात पर अमेरिका में शुल्क बढ़ाकर 500 फीसदी तक करना चाहिए।

अमेरिका ने पहले ही अगस्त से कई भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी का भारी शुल्क लगाया हुआ है, जिसमें 25 फीसदी शुल्क रूस से तेल खरीदने से जुड़ा दंड है।

वाणिज्य मंत्रालय के पूर्व अधिकारी और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि 500 फीसदी शुल्क से अमेरिका में भारत का सामान और सेवा निर्यात असल में बंद हो जाएगा, जो वर्तमान में सालाना 120 अरब डॉलर से ज्यादा है।

उन्होंने कहा, 'अमेरिका के सीमा शुल्क अधिकारी सामान पर शुल्क लगा सकते हैं लेकिन सेवाओं पर शुल्क लगाने का कोई कानूनी तरीका नहीं है। इसलिए भारतीय सेवाओं पर निर्यात शुल्क लगाने का मतलब अमेरिकी फर्मों से कर वसूलना होगा।'

आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस में ट्रेजरी प्रमुख हरसिमरन साहनी ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का असर व्यापार में रुकावटों से आगे बढ़कर भारत के लिए वृहद अर्थव्यवस्था तक बढ़ सकता है।

चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और पिछले तीन वर्षों में भारत धीरे-धीरे रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। ट्रंप का मानना है कि रूसी तेल से मिलने वाला धन रूस-यूक्रेन संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिन्हें अमेरिका से इस तरह के भारी शुल्क का सामना करना पड़ सकता है।

मार्च 2025 से भारत और अमेरिका व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं मगर अभी इसे साकार होने में समय लगेगा। इस बीच दोनों पक्ष ढांचागत व्यापार समझौता पर बातचीत कर रहे हैं और इसके अमल में आने से भारतीय निर्यातकों पर 50 फीसदी अमेरिकी शुल्क का बोझ कम हो सकता है। दोनों पक्षों के बीच आधा दर्जन से अधिक दौर की वार्ता के बावजूद बात नहीं बन पाई है।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को पेरिस में 'भारत-वीमर प्रारूप' की बैठक के बाद पोलैंड के उप प्रधान मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की, फ्रांस के विदेश मामलों के मंत्री जीन-नोएल बैरोट और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।

EDITORIAL

टैरिफ वार

अमेरिकी बाजारों में छह गुना तक महंगे हो सकते हैं भारतीय उत्पाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े बिल को पेश करने की मंजूरी दे दी है। यह बिल सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 नाम से है। अमेरिका में इस कानून के तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इस टैरिफ से लागू होने से भारत पर इसके संभावित असर और चुनौतियों पर नजर।

देश के लिए इसके मायने

1 अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात वाला देश है। रिपोर्ट के मुताबिक, 500% टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में छह गुना महंगे हो जाएंगे। इससे टेक्सटाइल, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद और ऑटो कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

- विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे भारत का अमेरिका को होने वाला निर्यात 86 अरब डॉलर से गिरकर 50 अरब डॉलर तक रह सकता है।

2 रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस समय रूस से अपनी जरूरत का लगभग 35-38% कच्चा तेल खरीद रहा है। अगर भारत दबाव में आकर रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करता है, तो उसे खाड़ी देशों या अमेरिका से महंगा तेल लेना होगा। इससे भारत के चालू खाता घाटे (सीएडी) में 6-7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे।

3 भारत के श्रम-प्रधान निर्यात क्षेत्र जैसे कपड़ा और हस्तशिल्प में हजारों नौकरियां जाने का खतरा पैदा होगा, क्योंकि भारतीय कंपनियां वियतनाम और बांग्लादेश के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी।

4 भारत को 1.4 अरब लोगों के लिए किफायती ईंधन (रूस से) और अपने उद्योगों के लिए अमेरिकी बाजार दोनों की जरूरत है। इनमें से किसी एक को चुनना मुश्किल होगा।

किस पर कितना प्रभाव

कपड़ा और हस्तशिल्प

50% टैरिफ से यहां निर्यात में 30% से अधिक गिरावट आई थी। 500% टैरिफ लगता है तो निर्यात के पूरी तरह ठप होने का खतरा।

रत्न और आभूषण

500% टैरिफ सूरत की पॉलिशिंग इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय हीरों का सबसे बड़ा खरीदार है। इस टैरिफ से अमेरिका में एक भारतीय हीरा 6 गुना महंगा हो जाएगा।

होम टेक्सटाइल-कालीन

होम टेक्सटाइल का 60% व कालीन का 50% निर्यात अमेरिका को जाता है। टैरिफ से इसकी बिक्री घटेगी।

कृषि क्षेत्र

अमेरिका हर साल 3,00,000 से 3,50,000 टन बासमती चावल भारत से खरीदता है। 500 फीसदी तक टैरिफ से बासमती, तिलहन, अरंडी का तेल और मसाले जैसे निर्यात पर भारी असर पड़ेगा।

बढ़ोतरी के बाद भारतीय वस्तुओं पर कितना शुल्क

उत्पाद	पुराना शुल्क	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क	अमेरिका को निर्यात में हिस्सेदारी	कुल कारोबार
सिले कपडे	13.9	63.9	500	34.5	23000
बुने कपडे	10.3	60.3	500	32.2	23000
सूती कपड़ा	9.0	60.3	500	48.4	23000
कार्बनिक रसायन	4.0	54	500	13.2	23000
जवेलरी, गोल्ड	2.1	52.1	500	40.0	87730
कालीन	2.9	52.9	500	58.6	11000
मशीन अन्य उपकरण	1.1	51.3	500	20.0	59000
झींगा	0.0	60	500	32.4	17523
फर्नीचर गद्दे-मैट्रेस	2.3	52.3	500	44.8	9637

शुल्क का आंकड़ा प्रतिशत में, कुल कारोबार करोड़ रुपये में

स्रोत : जीटीआरआई विश्लेषण डीजीसीआईएस डाटा और अमेरिका टैरिफ सूचनाओं के आधार पर

तुलनात्मक प्रभाव: 50% बनाम 500%

सेक्टर	50% टैरिफ का असर (2025)	500% टैरिफ का संभावित खतरा
निर्यात मूल्य	86 अरब डॉलर से गिरकर 55 अरब डॉलर रह गया	15-20 अरब डॉलर तक गिरने की आशंका
प्रमुख निर्यात	स्मार्टफोन्स, कपड़े, हीरे पर असर	सभी भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार से बाहर
जीडीपी	लगभग 0.5% - 1.0% की गिरावट	2% से अधिक की बड़ी आर्थिक गिरावट
व्यापारिक संबंध	तनावपूर्ण पर बातचीत जारी	ट्रेड वॉर जैसी स्थिति, चीन और रूस के करीब जाने की मजबूरी

वैश्विक संस्था की लगातार बढ़ती उपेक्षा

आज की दुनिया एक गहरे नैतिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है, जहां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है और नियम आधारित विश्व व्यवस्था केवल कागजों और भाषणों तक सिमटकर रह गई है। जिन सिद्धांतों पर यह व्यवस्था खड़ी थी, आज वही सिद्धांत सबसे अधिक उपेक्षित नजर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होते, बल्कि उनकी व्याख्या ताकत और हितों के तराजू पर की जाती है। जब नियम शक्तिशाली देशों के हितों के अनुकूल होते हैं, तब उन्हें 'वैश्विक व्यवस्था' कहा जाता है, और जब वही नियम उनके रास्ते में बाधा बनते हैं, तब उन्हें नजरंदाज कर दिया जाता है या तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र से उम्मीद थी कि वेनेजुएला मसले पर वह सख्त रुख अपनाएगा, लेकिन वह मूक ही बना है।

हालिया उदाहरण बताते हैं कि किस तरह आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और बाहरी हस्तक्षेप को लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आड़ में हथियार बना लिया गया है। किसी देश की सरकार की वैधता पर सवाल उठाना, समानांतर सत्ता को मान्यता देना, संसाधनों पर नियंत्रण की इच्छा और जनता को मजबूर कर देने वाले प्रतिबंध, ये सब उस व्यवस्था का चेहरा हैं, जो खुद को नियम आधारित कहती है। वेनेजुएला के संदर्भ में सत्ता-परिवर्तन की खुली बातें, तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर पकड़ की लालसा और धमकी भरी भाषा यह बताती है कि आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता नहीं, बल्कि ताकत निर्णायक बनती जा रही है। यही प्रवृत्ति दुनिया के अन्य हिस्सों में भी दिखती है, जहां ग्रीनलैंड, क्यूबा, कोलंबिया या मेक्सिको जैसे देशों के बारे में अल्टीमेटम की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मानो वे संप्रभु राष्ट्र नहीं हों।

अगर यही रुख जारी रहा, तो छोटे और कमजोर देशों के लिए अपनी स्वतंत्रता और पहचान बचा पाना बेहद कठिन हो जाएगा। यह स्थिति केवल किसी एक देश या क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब नियम टूटते हैं और शक्ति ही न्याय बन जाती है, तब दुनिया अराजकता, युद्ध व हिंसा के अंधेरे में डूब जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से नैतिक आधार दिया जाए, कानून को ताकत से ऊपर रखा जाए और यह स्वीकार किया जाए कि सच्ची वैश्विक शांति किसी एक देश के वर्चस्व से नहीं, बल्कि समानता, सम्मान और न्याय से ही संभव है। अन्यथा, इतिहास खुद को एक बार फिर विनाशकारी रूप में दोहराएगा।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

संयुक्त राष्ट्र

समय के साथ बढ़ रही उपयोगिता

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर रात के अंधेरे में हमला किया और उसके राष्ट्रपति को पत्नी सहित अपमानजनक ढंग से अपने देश ले गए। इससे विश्व व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। यह वही व्यवस्था है, जिसे संचालित करने की बड़ी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के पास है। आरोप लगाया जा रहा है कि यह संस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। हालांकि, मैं इससे सहमत नहीं। अलबत्ता, इस घटना के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई, जिसमें महासचिव का यह कहना उचित था कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि सभी सदस्य देश इसके चार्टर का पालन करें, इसलिए यह कहना गलत होगा कि इस विश्वस्तरीय संस्था की उपादेयता समाप्त हो गई है।

वास्तव में, दोष इस संस्था में नहीं, इसके कुछ सदस्य देशों में है। वे इसके मूल्यों को मानने से इनकार करने लगे हैं। यही कारण है कि यूएन की बैठक में मतभेद भी दिखे। रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों ने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की, जबकि दक्षिण अफ्रीका, ईरान जैसे राष्ट्रों ने खुलकर कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय कानून सब पर समान रूप से लागू नहीं होंगे, तो पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। उनकी चिंता जायज है। सवाल यह भी है कि क्या इस संस्था का कोई विकल्प आज के समय में है? गौरतलब है कि वीटो अधिकार देशों को मिला था, उनके नेताओं को नहीं, लेकिन ये नेता वीटो का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। ऐसे में, जरूरी यह है कि इस संस्था में सुधार हो, न कि इसकी प्रासंगिकता खारिज कर दी जाए।

किसी महत्वपूर्ण कामकाजी संस्था पर आक्षेप लगा देना, उसके महत्व को निर्मूल्य कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसकी स्थापना, उसका नियमित सुचारू संचालन कदापि सुगम नहीं होता। संस्था को दोषी सिद्ध करने से उस पर काबिज दोषी व्यक्ति का दोष कमतर या शून्य हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर उंगली उठाते समय क्या आप डोनाल्ड ट्रंप की मूढ़ता और हठधर्मिता को कम नहीं कर रहे होते हैं? संयुक्त राष्ट्र के पास अपना कोष नहीं है, उसकी निर्भरता सदस्य राष्ट्रों पर है। वास्तव में, कुछ सदस्य राष्ट्र उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। लिहाजा, इसमें दोष ढूंढ़कर इसे बदनाम करने या नष्टप्राय करने के बजाय इसे कैसे और प्रभावशाली, सक्षम व न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। बदलते भू-राजनीति के इस दौर में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है। हमें इसमें सुधार की वकालत करनी चाहिए।

दिनेश सिंह, चिकित्सक

विनय सिन्हा

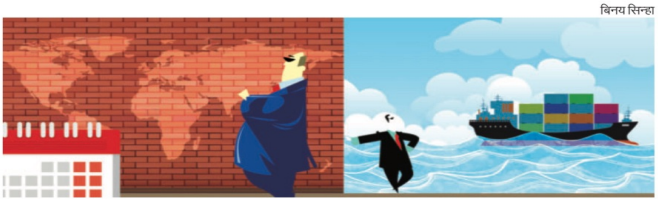

अमेरिका, यूरोपीय संघ के साथ समझौतों पर संकट

दोनों ही मामलों में भारत को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। बता रहे हैं आर जगन्नाथन

भारतीय अधिकारी समय-समय पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की संभावना जताते रहते हैं। विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफिंग में कुछ महीने पहले कहा गया था कि दोनों समझौतों की दिशा में इस इरादे से आगे बढ़ा जा रहा है कि निष्पक्ष, संतुलित और साझा लाभ वाला समझौता किया जा सके।

हाल ही में ओमान और न्यूजीलैंड के साथ शीघ्रता से समझौते किए जाने के बाद शायद यह धारणा बना कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ भी जल्दी समझौते हो सकते हैं। खासकर यूरोपीय संघ के साथ क्योंकि यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर नई दिल्ली में होंगे। उनका यहां होना इस समझौते की शुरुआत का माकूल वक्त हो सकता है।

कुछ दिन पहले अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की ताकि व्यापार समझौते को जल्द अंजाम दिया जा सके। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि समझौता लगभग हो ही गया है और वह देरी से हैरान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समझौता इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा नहीं हुआ तो उन्हें आश्चर्य होगा।

आज अमेरिका के साथ समझौते को लेकर आशान्वित होने की वजहें कम हैं और इसका कारण हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के लिए बार-बार लक्ष्य बदले हैं। शुरुआत इस मांग से हुई कि भारत अमेरिका से अधिक खरीद कर व्यापार घाटे को कम करे। फिर यह पाकिस्तान के साथ पिछले मई में युद्धविराम कराने में उनकी कथित भूमिका को स्वीकार करने पर आ गया। उसके बाद यह रूसी तेल पर केंद्रित हो गया और दो दिन पहले उन्होंने कहा कि यह सब केवल भारत द्वारा उन्हें खुश करने से संबंधित है।

भारत, अमेरिका के साथ एक अच्छा व्यापार समझौता करना चाहता है, लेकिन जिस समझौते पर हमें बातचीत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वह व्हाइट हाउस में बैठे एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के साथ एक संदिग्ध सौदा है। अमेरिका यदि अपनी संवैधानिक समझ में लौटे और ट्रंप की राजनीतिक किस्मत पलटने लगे या आने वाले महीनों में किसी दिन उनका मिजाज बदल जाए तो व्यापार समझौते की अहमियत उस कागज के बराबर भी नहीं होगी जिस पर वह लिखा गया है।

संभव है कि ये समझौते जल्दी हों या शायद इनमें समय लगे। परंतु देश के नीति निर्माताओं और बाजार का यही मानना है कि इनके पूरा होने में समय लगेगा। अब वक्त आ गया है कि हम बुरे से बुरे परिदृश्य की तैयारी रखें। ट्रंप के साथ किया गया व्यापार समझौता शायद उनके ही देश में न्यायिक परीक्षा पर खरा न उतरे। अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों व्यापक आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक उथलपुथल से गुजर रहे हैं और अलग-अलग विचारधाराओं की लॉबी एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रही हैं।

अमेरिका में, ट्रंप के चुनाव के बाद कुलीन वर्ग की सहमति का टूटना और 2025 में ज्यादातर समय उनका अस्थिर व्यवहार राजनीतिक सहमति को कठिन बना देता है। उनका अपना 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मागा) समर्थक आधार यथार्थवादियों और कट्टरपंथी दक्षिणपंथी विचारधारकों के बीच बंटा हुआ है, जो भारत को किसी भी प्रकार की रियायत दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं, भले ही बड़ी तकनीकी कंपनियां भारत की ओर से विशेषकर एच-1बी वीजा और सेवाओं को लेकर दबाव डाल रही हों। अक्टूबर में अमेरिकी राजदूत के रूप में पुष्टि होने के बावजूद, सर्जियो गोर ने अभी तक भारत में अपना कार्यभार नहीं संभाला है।

ट्रंप प्रशासन एपस्टीन फाइल्स के जारी होने के राजनीतिक परिणामों से जूझ रहा है। सेक्स ट्रैफिकर जेफ्री एपस्टीन के साथ ट्रंप के कथित करीबी संबंधों के कुछ विवरण उजागर हुए। एपस्टीन महिलाओं और युवा लड़कियों की सेक्स-तस्करी के आरोपों पर मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने 2019 में जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली। एपस्टीन फाइलें केवल ट्रंप से ही संबंधित नहीं हैं, बल्कि उन पूरे राजनेताओं और व्यापारियों की श्रेणी से जुड़ी हैं जो अभिजात वर्ग का हिस्सा हैं। अमेरिकी 'डीप स्टेट' को जनता का ध्यान एपस्टीन पर अत्यधिक केंद्रित होने से हटाने के लिए व्यापार और अन्य बाहरी संघर्षों का विचलन चाहिए। यही कारण है कि ट्रंप का ध्यान ग्रीनलैंड पर और वेनेजुएला पर हमलों पर रहा। अमेरिका ने एक डकैत की तरह व्यवहार किया और वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का अपहरण कर उन्हें अमेरिका भेज दिया।

दूसरी तरफ यूरोप, यूक्रेन मामले में खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसने हाल ही में रूसी परिसंपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज करने का निर्णय लिया, जिससे उसकी वित्तीय प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय विश्वास को आघात पहुंचा। यूरोपीय संघ गहराई से विभाजित है। एक ओर वे देश हैं जो यूक्रेन को पूरी तरह समर्थन देना चाहते हैं, और दूसरी ओर वे हैं जो नहीं चाहते कि युद्ध अंतहीन रूप से चलता रहे और विकास तथा रोजगार के लिए आवश्यक संसाधनों को निचोड़ता रहे।

अब यूरोप को जब ट्रंप के उपहास और ग्रीनलैंड को लेकर उनकी धमकियों का सामना करना पड़ रहा है तो यूरोप यूक्रेन को लेकर और अधिक अस्थिर प्रतीत हो रहा है। ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ समझौता करने और विफल रहने पर भारत को दंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो और यूरोपीय संघ दोनों का भविष्य अब कुछ संदेह में है। दिसंबर में, यूरोपीय संघ लैटिन अमेरिकी मर्कोसुर ब्लॉक के साथ अपना सबसे बड़ा व्यापार समझौता करने वाला था, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अंतिम क्षण में अड़ंगा डाल दिया, जिसके कारण यह समझौता एक महीने के लिए स्थगित हो गया। यदि यह समझौता हस्ताक्षरित होता है, तो यह दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉकों में से एक का निर्माण करेगा। यह यूरोपीय संघ को मर्कोसुर से जोड़ेगा, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे शामिल हैं।

पिछले 20 वर्षों में रुक-रुक कर हुई बातचीत से तैयार यह समझौता अभी भी अधर में लटका हुआ है और यूरोपीय संघ के आंतरिक मतभेदों का बंधक बना हुआ है। फ्रांस, पोलैंड और इटली के किसान इस समझौते के मुख्य अवरोधक बताए जाते हैं, हालांकि कहा जाता है कि मेलोनी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को आश्वासन दिया है कि जैसे ही वह अपने किसानों को राजी कर लेंगी, हस्ताक्षर कर देंगी। वह अपने किसानों के लिए यूरोपीय संघ से ज्यादा सहयोग हासिल करने की कोशिश भी कर सकती हैं ताकि अपना वीटो हटा सकें। लेकिन कमजोर वृद्धि के माहौल में यूरोपीय संघ की वित्तीय स्थिति भी दबाव में है। यही वह अमेरिकी और यूरोपीय संघ का संदर्भ है जिसमें भारत व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहा है। यह मान लेना उचित नहीं होगा कि यूरोपीय संघ सामूहिक रूप से समझौते के लिए अमेरिका से अधिक उत्सुक है। दोनों ही आंतरिक झगड़ों और विरोध से जूझ रहे हैं। वे भीतर ही राजनीतिक लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और जैसे-जैसे यूरोपीय संघ में दक्षिणपंथी राजनीति मजबूत होती जा रही है, वर्तमान सीमित राजनीतिक सहमति भी कमजोर दिखने लगेगी।

भारत के लिए यह बुद्धिमानी होगी कि वह खराब हालात को देखते हुए योजना बनाए। 2026 की शुरुआत में बड़े व्यापारिक समझौतों की भविष्यवाणी धुंधली दिखाई देती है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

हरित ऊर्जा

गजेंद्र सिंह
लोक नीति विश्लेषक

भविष्य की चिंता में घुटता वर्तमान

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए हरित ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, परंतु इसके संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभावों की चिंता भी अभी से ही करनी होगी

राजस्थान समेत देश के अन्य कई क्षेत्रों में खेतों में बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं सोलर पैनल। फाइल

उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में राजस्थान और गुजरात में सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर दिये गया एक निर्णय ऊर्जा नीति, जैव-विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्णय विलुप्ति की कगार पर खड़े गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) और उसके प्राकृतिक आवास की रक्षा के संदर्भ में आया है, जिसने 'हरित ऊर्जा' की वर्तमान विकास-परिभाषा पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। अकेले राजस्थान में 26,452 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जिसके लिए लगभग 1.32 लाख एकड़ भूमि का उपयोग किया गया है। इस विस्तार की पर्यावरणीय कीमत भी भारी रही है, अब तक लगभग 26 लाख पेड़ और 40 लाख झाड़ियां सौर परियोजनाओं के लिए काटी जा चुकी हैं।

इस 'हरित ऊर्जा' के बादे के पीछे गंभीर पारिस्थितिक और सामाजिक चुनौतियां भी हैं। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के कई गांवों में ग्रामीणों ने लगभग 90 प्रतिशत भूमि कंपनियों को बेच दी है। कंपनी द्वारा किए गए भुगतान का लाभ केवल एक-दो वर्षों तक ही रहता है, जिसके बाद ग्रामीणों को रोजगार की तलाश के लिए पलायन करना पड़ता है। इसके साथ ही पशुओं के चारे के लिए भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है, जिससे पशुपालन व्यवसाय और उससे जुड़ी आजीविका समाप्त होने के कगार पर है। हालांकि, इन परियोजनाओं के बावजूद सरकार और कंपनियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र में रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और अन्य सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों में कोई ठोस रुचि दिखाई नहीं दे रही है।

वैसे स्थानीय ग्रामीणों को अल्पकालिक आर्थिक लाभ ही मिलते हैं, जबकि दीर्घकालिक आजीविका विकल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल-संरक्षण जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका नकारात्मक प्रभाव समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर पड़ रहा है। जल संसाधनों पर भी भारी दबाव है। इस क्षेत्र में संयंत्रों के कारण स्थानीय तापमान में भी वृद्धि हुई है और लाखों पेड़ कटने से पक्षी, तितलियां और अन्य कीट-पतंगे गायब हो गए हैं। परिणामस्वरूप प्राकृतिक परागण ठप हो गया है और किसानों को कृत्रिम परागण करना पड़ रहा है। कृषि उत्पादन पैदावार में भी गिरावट आई है।

इसी पृष्ठभूमि में पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर स्पष्ट किया कि नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य आवश्यक हैं, लेकिन वे बिलुप्तप्राय प्रजातियों और नाजुक पारिस्थितिकी की कीमत पर नहीं साधे जा सकते। अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी इसी दिशा में चेतावनी देते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बड़े सौर फार्मों को स्थानीय वनस्पति, जीव-जंतु और भूजल पर गंभीर प्रभाव के कारण कानूनी और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कुछ परियोजनाओं को निलंबित या संशोधित करना पड़ा। चीन और जर्मनी में भी बड़े पैमाने पर सौर पार्कों के कारण मिट्टी कटाव, जल संरक्षण और जैव विविधता पर दबाव देखा गया।

इसके विपरीत, स्पेन और आस्ट्रेलिया में सौर-कृषि मिश्रित माडल अपनाए गए हैं, जिसमें सौर पैनलों के नीचे कृषि और पशुपालन किया जाता है। इससे ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ भूमि का संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और स्थानीय किसानों की आय सुनिश्चित होती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सौर ऊर्जा का विकास तभी सतत और पर्यावरण-अनुकूल हो सकता है जब परियोजनाओं के डिजाइन में पारिस्थितिकी, जल प्रबंधन और स्थानीय समाज की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सौर ऊर्जा परियोजना से पहले भूमि उपयोग के सामाजिक-आर्थिक और कृषि मूल्य का गहन अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर सौर संयंत्रों के कारण पेड़ों की कटाई, पारिस्थितिकी संतुलन में गिरावट और स्थानीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कंपनियों के लिए कठोर नियम लागू किए जाएं, ताकि वे स्थानीय रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक निवेश को अनिवार्य रूप से अपनाएं। सौर प्लांटों के खाली हिस्सों को चरागाह, सौर-कृषि माडल या 'आक्सीजन बैंक' के रूप में विकसित किया जाए। राजस्थान में खेजड़ी जैसे राज्य वृक्ष को सख्त कानूनी संरक्षण मिले और जल-खपत कम करने वाली तकनीकों को अनिवार्य किया जाए। पेड़ काटने पर जुर्माना वास्तविक पर्यावरणीय मूल्यांकन पर आधारित हो। सौर पैनलों की सफाई और ठंडा करने के लिए कम जल खपत वाली तकनीक अपनाई जाए, संयंत्रों के आसपास हरित पट्टी विकसित की जाए और परियोजना शुरू होने के बाद पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव की नियंत्रित निगरानी कर रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन और जनता के लिए पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराई जाए।

इस प्रकार के प्रयासों से सौर ऊर्जा परियोजनाएं न केवल 'हरित ऊर्जा' का उदाहरण बन सकती हैं, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण समाज के लिए भी सतत योगदान सुनिश्चित कर सकती हैं।